भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3975
उत्तर देने की तारीख 12 अगस्त, 2026

उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना

3975. **श्री राजेश वर्मा:**
श्री अतुल गर्ग:
श्रीमती शांभवी:
श्री अरुण भारती:
डॉ. लता वानखेड़े:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) वर्ष 2025-26 के दौरान बिहार और मध्य प्रदेश में दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए 'उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन' (पीएलआई) योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले विनिर्माण उद्यमों की कुल संख्या कितनी है;
(ख) उक्त केंद्रीय पहल के अंतर्गत राउटर, स्विच और ऑप्टिकल फाइबर केबल के विनिर्माण के लिए बिहार के औद्योगिक क्षेत्रों में कुल कितना पूंजीगत निवेश सृजित हुआ है;
(ग) विगत एक वर्ष के दौरान अपने वृद्धिशील उत्पादन लक्ष्यों को पूरा/हासिल करने पर बिहार में स्थित दूरसंचार उपकरण निर्माताओं को संवितरित की गई वित्तीय प्रोत्साहन राशि कितनी है;
(घ) क्या मंत्रालय ने बिहार में पर्याप्त इलेक्ट्रॉनिक घटक आपूर्ति श्रृंखलाओं की कमी को ध्यान में रखा है, जिससे स्थानीय निर्माताओं को आयात पर निर्भर होने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ.) सरकार द्वारा बिहार और मध्य प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता प्रदान करने के लिए समर्पित दूरसंचार विनिर्माण क्लस्टर स्थापित करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (ग): टेलीकॉम और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम कंपनी स्तर पर लागू की जाती है और इसके प्रोत्साहन अनुमोदित लाभार्थी कंपनियों द्वारा निर्धारित निवेश और क्रमिक बिक्री लक्ष्यों को प्राप्त करने से जुड़े हैं। स्कीम के तहत प्रोत्साहनों का राज्य-वार आवंटन परिकल्पित नहीं है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पीएलआई स्कीम के तहत किसी भी अनुमोदित लाभार्थी कंपनी की विनिर्माण इकाई बिहार और मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है।

(घ) सरकार ने बिहार सहित पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक घटकों और उप-संयोजनों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण स्कीम (ईसीएमएस) को अनुमोदन प्रदान किया है।

(ङ) सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से ग्वालियर, मध्य प्रदेश में एक टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (टीएमजेड) की स्थापना को अनुमोदन प्रदान किया है। वर्तमान में, सरकार के पास बिहार या मध्य प्रदेश में किसी अन्य टेलीकॉम विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****